

provision of payment of pension to former Members of Parliament; and

(b) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b). Representations have been received both for repealing the provisions regarding the granting of pension to ex-Members of Parliament and for liberalising them. The whole question is under consideration.

**Construction of P & T Building at Sewagram**

569. SHRI SANTOSHRAO GODE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether a foundation stone of a Posts and Telegraphs Building was laid by his predecessor Shri Bahuguna at Sewagram;

(b) if so, the date of laying the foundation stone;

(c) the time by which the building will be completed; and

(d) the reasons for delay in completing the building?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b). The foundation stone for a Post Office building at Sewagram was laid by Shri H. N. Bahuguna, the then Minister of Communications, on 4th August, 1973.

(c) The building is likely to be completed by the end of March, 1978.

(d) The Secretary of the Sewagram Ashram had offered the land for construction of the P.O. buildings. But, later on it was learnt that transfer of land to the P&T Department could not take place without a "no objection certificate" from the Charity-Commissioner, Bombay. The various

formalities for the transfer of land were completed and possession of land was taken over only in February, 1977.

घापात स्थिति के दौरान नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों की संख्या

570. श्री रामानन्द तिवारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घापात स्थिति के दौरान राज्य स्तर पर कितने व्यक्तियों की जबरदस्ती नसबन्दी की गई; और

(ख) जबरन नसबन्दी के शिकार व्यक्तियों को किसी रूप में मुआवजा देने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) अभी तक आंध्र प्रदेश, असम, नागालैण्ड, मिक्किम और त्रिपुरा राज्य सरकारों तथा अरुणाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली संघ शामिल क्षेत्र प्रशासनों में जानकारी प्राप्त हुई है और इन सभी में सूचित किया है कि उनके अधीन किसी भी व्यक्ति की जबरदस्ती नसबन्दी नहीं की गई। जेप राज्यों तथा संघ शामिल क्षेत्रों में जानकारी प्रतीक्षित है।

(ख) केन्द्र सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को कोई नकद मुआवजा देने की योजना नहीं बनाई है यद्यपि उनके लिए आवश्यक उपचार तथा चार्ज पर पुनः नस जोड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकारों संघ शामिल क्षेत्रों को निर्देश दिये हैं।

**Help sought by Sri Lanka**

571. SHRI OM PRAKASH TYAGI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government of Sri Lanka has sought help to check insurgent activities; and